

# डेलर्स रिपोर्ट पर पुनः चर्चा : भारत के लिए सबक

अर्चना मेहेंदले

आज भारत की शिक्षा प्रणाली सुधार के दौर से गुजर रही है और विविध स्रोतों से नीतिगत सिफारिशें अपने प्रतिस्पर्धी दावों के साथ उभरकर सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन की बजाय भ्रमित होने की सम्भावना बढ़ गई है। ऐसे में डेलर्स रिपोर्ट पर पुनः नजर डालना उचित प्रतीत होता है। डेलर्स रिपोर्ट का शीर्षक है 'लर्निंग - द ट्रेशर विदिन' (1996)। इसमें मौजूदा शैक्षिक चुनौतियों और व्यक्ति व सामाजिक विकास में शिक्षा की भूमिका का प्रखर विश्लेषण किया गया है। यूनेस्को ने जैक्स डेलर्स की अध्यक्षता में बीसवीं सदी के लिए शिक्षा पर एक अन्तरराष्ट्रीय आयोग का गठन किया। इस आयोग को वास्तविकताओं की जाँच करने और यह प्रस्तावित करने का कार्य सौंपा गया कि शिक्षा प्रणाली किस प्रकार से नई सदी में पैदा होने वाली अधिगम सम्बन्धी सरोकारों को दूर कर सकती है। इस कार्य को उन अन्तरराष्ट्रीय प्रयासों की निरन्तरता के रूप में देखा जाना चाहिए जो जोमटेन में सभी के लिए शिक्षा की विश्व घोषणा (1990) को अपनाने के साथ शुरू हुई और जिसमें विश्व निर्धनता, अज्ञान, बहिष्करण, उत्पीड़न व युद्ध को कम करने और शान्ति, स्वतंत्रता, तथा सामाजिक न्याय को बहाल करने के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया था। नई सदी का एक दशक से अधिक समय समाप्त हो चुका है और अब समय आ गया है कि हम इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट की मुख्य बातों की समीक्षा करें और यह समझने का प्रयास करें कि वर्तमान भारतीय शिक्षा क्षेत्र में जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं, उस प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने के लिए वे कितनी प्रासंगिक हैं।

## अधिगमशील समाज का निर्माण

डेलर्स की रिपोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया कि सीखने को कैसे सीखा जाए-यह बात अधिगमशील समाज के निर्माण का सार है जहाँ हर एक व्यक्ति शिक्षक भी होगा और शिक्षार्थी भी। यह विचार पहली यूनेस्को रिपोर्ट 'लर्निंग टु बी' (1972) पर आधारित है। इसे एडगर फाउर की अध्यक्षता में तैयार किया गया जिसमें सार्वभौमिक रूप से मान्य ऐसे निष्कर्ष और सिफारिशें दी गईं जिन्हें राष्ट्रीय रूप से लागू किया जा सके। यह एक कठिन कार्य था। इसमें कुछ नए परिप्रेक्ष्यों की पेशकश की गई, जैसे कि शिक्षा ''बच्चों और युवाओं के लिए स्नेह की अभिव्यक्ति है, जिनका हमें समाज में स्वागत करना है, और निस्सन्देह उन्हें वह स्थान दिलाना है जो वास्तव में उनका अधिकार है (पृष्ठ 12)।'' इसमें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुखता और शिक्षा की भूमिका को महत्व देते हुए कहा गया कि,'' कोई भी चीज औपचारिक शिक्षा प्रणाली का स्थान नहीं ले सकती, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान के कई रूपों से परिचित करवाया जाता है''(पृष्ठ 19) और यह कि ''शिक्षक-छात्र सम्बन्ध का कोई विकल्प नहीं है'' (पृष्ठ 19) और शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह ''विद्यार्थियों को वह ज्ञान प्रदान करे जिसे मानव जाति ने अपने और प्रकृति के बारे में हासिल किया है और इसने जो कुछ भी बनाया या जिसका भी आविष्कार किया है उसके महत्व के बारे में बताए'' (पृष्ठ 20)। रिपोर्ट के मुख्य कार्यों में से एक यह भी था कि आजीवन शिक्षा और ''अधिगमशील समाज की ओर बढ़ने की आवश्यकता'' पर जोर दे। डेलर्स की रिपोर्ट का शीर्षक इस मुख्य प्रस्ताव से लिया गया है कि''प्रत्येक व्यक्ति में जो प्रतिभा किसी गड़े हुए खजाने की तरह छिपी हुई होती है उसे अनदेखा नहीं छोड़ना चाहिए'' (पृष्ठ 21)। इनमें स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना, शारीरिक क्षमता, सौन्दर्य बोध, दूसरों के साथ बातचीत करने की योग्यता, नेतृत्व और ऐसे ही अन्य गुण शामिल हैं।

इस रिपोर्ट में सात तरह के 'तनावों' की बात कही गई है, जिन पर इक्कीसवीं शताब्दी में विजय पानी है। चार स्तम्भ प्रस्तावित किए हैं जो अधिगमशील समाज के निर्माण में सहायता करेंगे (देखें बाक्स 1 और 2)। इन्हें रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ माना जाता है। यह रिपोर्ट स्थायी मानव विकास, लोकतंत्र और आपसी समझ के विजन की बात करती है और इन्हें पाने के लिए जिन सात तनावों को दूर करना है, उनके बारे में बताती है। इस रिपोर्ट में तनावों को जीतने के बारे में कोई मार्ग नहीं सुझाया गया है, बल्कि उन विभिन्न कारकों पर ध्यान दिया गया है जो तनाव में योगदान देते हैं और जिनसे नीति निर्माताओं को निपटना है। रिपोर्ट के अनुसार 'नई मानसिकता' लाने के लिए चार स्तम्भों में से सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ है 'एक साथ रहना सीखना' और इससे ही आपसी समझ और पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ती है। अन्य तीन स्तम्भ हैं 'जानना सीखना', 'करना सीखना' और 'होना सीखना'; जिन्हें 'एक साथ रहना सीखने' का आधार माना गया है।

| जिन तनावों पर विजय प्राप्त करनी है |
| --- |
| 1. वैश्विक और स्थानीय |
| 2. सार्वभौमिक और व्यक्तिगत |
| 3. परम्परा और आधुनिकता |
| 4. दीर्घकालिक और अल्पकालिक विचार |
| 5. प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता और अवसर की समानता का सरोकार |
| 6. ज्ञान का असाधारण विस्तार और उसे आत्मसात करने की मनुष्य की क्षमता |
| 7. आध्यात्मिक और भौतिक |

बाक्स 1

भाषा और उपयोग में लाए जाने वाले शैक्षणिक उपकरणों की समीक्षा करनी होगी। लेकिन इस तरह के टुकड़े-टुकड़े दृष्टिकोण की बजाय शिक्षा की एक नई नीति स्थापित करनी होगी जो पहले की नीतियों से वे प्रासंगिक विचार ले जिन्हें या तो उपेक्षित किया गया या आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया। साथ ही यह नीति ऐसी होनी चाहिए जो तात्कालिक चुनौतियों से परे जाकर अग्रदर्शी भी हो।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ. 2005) व्यापक और विविध रूपों से 'तनावों' और 'स्तम्भों' दोनों का उल्लेख करती है। पाठ्यचर्या के उद्देश्यों में वैश्विक और स्थानीय

| अधिगमशील समाज के निर्माण के लिए प्रस्तावित चार स्तम्भ | |
| --- | --- |
| 1. जानने के लिए सीखना | इसमें ज्ञान का व्यापक विस्तार और गहराई, अधिगम को सीखना शामिल है |
| 2. करने के लिए सीखना | इसमें व्यावसायिक और सामाजिक कौशल का अधिग्रहण शामिल है |
| 3. एक साथ रहने के लिए सीखना | इसमें परस्पर निर्भरता की कद्र करना आ जाता है |
| 4. अस्तित्व के लिए सीखना | इसमें व्यक्तिगत स्वायत्तता, विवेकपूर्ण निर्णय और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की क्षमता शामिल है |

बाक्स 2

सन्तुलन का तनाव एवं तेजी से विस्तारशील ज्ञान के कारण उसे आत्मसात करने की चुनौती को एन.सी.एफ. में न केवल नीति निर्माताओं ने वरन शिक्षकों और शैक्षिक पेशेवरों ने भी स्वीकार किया है।

सार्वभौमिक और आधुनिक दबावों के कारण व्यक्तिगत और पारम्परिक प्रणालियों के संरक्षण की चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह कार्य जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों द्वारा किया गया है विशेष रूप से भाषाओं, स्थानीय संस्कृति, कला, शिल्प और पारम्परिक कौशलों के संरक्षण के सम्बन्ध में। प्रतिस्पर्धा और अवसर की समानता को बढ़ावा देने के बीच जो तनाव है, वह एक विवादास्पद मुद्दा है, विशेष रूप से उच्च शिक्षा में, हालाँकि भारतीय संविधान सकारात्मक कार्रवाई और अवसर की समानता प्रदान करता है।

दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों के बीच सन्तुलन एक और 'तनाव' है जिससे नीति निर्माता लगातार जूझते रहते हैं और राजनीतिक होड़ में अक्सर अल्पकालिक मुद्दों और एजेंडा को प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्य बयानबाजी तक सीमित रहते हैं, उनमें कार्य परिचालन के ठोस रास्ते नहीं दिखाए जाते और इसलिए राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र ऐसे दीर्घकालिक लक्ष्यों की कल्पना को समझने

## भारत के सन्दर्भ में नीति की प्रासंगिकता

हालाँकि डेलर्स रिपोर्ट को काफी महत्वपूर्ण समीक्षा प्राप्त हुई और इसकी सिफारिशें भी की गईं, लेकिन अकादमिक समुदाय या नीति निर्माताओं ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। ऐसा शायद इसलिए कि नब्बे के दशक के मध्य में भारत एक अलग प्रकार के संघर्षों और परिवर्तनों से गुजर रहा था, जिसमें नए बाह्य वित्त पोषित मिशन मोड वाले कार्यक्रमों को शामिल किया गया था जैसे कि सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति, शिक्षा प्रशासन में सुधार, विकेन्द्रीकरण और शिक्षा के क्षेत्र को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए खोलना आदि। डेलर्स रिपोर्ट इन बुनियादी चुनौतियों को सन्तुष्ट नहीं कर पाई और इसलिए नीतिगत एजेंडा पर प्रभाव नहीं डाल सकी। तो हमें यह सवाल पूछना है कि क्या अब हम डेलर्स रिपोर्ट में प्रस्तावित अधिगमशील समाज और शिक्षा के बृहत उद्देश्य अपनाने के लिए तैयार हैं?

इस तेजी से बदलते वैश्विक समाज में शैक्षिक तंत्र को जिस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए, उसके बारे में इस रिपोर्ट का योगदान काफी गहन है। नीति के स्तर पर इन विचारों के साथ जुड़ने के लिए शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षा के दर्शन, पाठ्यचर्या,

में विफल होते हैं और इन लक्ष्यों को उनका समर्थन नहीं प्राप्त हो पाता। परिणामस्वरूप, नीति निर्माण की कोई भी प्रक्रिया हालाँकि सहज रूप से भविष्य की दिशाओं का मार्गदर्शन करने के लिए होती है, लेकिन वास्तव में वह तात्कालिक समस्याओं के निपटान के परे नहीं जा पाती। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि तनावों को चरम स्थिति या 'दोनों में से या तो यह या वह' के रूप में न लिया जाए बल्कि एक निरन्तरता के रूप में लिया जाए जिसमें चुनौती लगातार काम करने और उस निरन्तरता में अपनी स्थिति को समझने की होगी। यहाँ यह भी स्पष्ट करने की आवश्यकता हो सकती है कि निरन्तरता की यह व्यापक रूपरेखा एक ऐसी आधिकारिक नीति के माध्यम से तय की जाए जो विभिन्न राज्य और गैर-राज्य कर्ताओं पर बाध्यकारी हो और या निरन्तरता पर विभिन्न स्थितियों को विकल्प की एक सूची के रूप में पेश किया जाए जिसमें विकल्प माता-पिता का होगा कि इन प्रतिस्पर्धात्मक विकल्पों या 'तनाव' के बीच मिश्रण कैसे करें।

दूसरे शब्दों में, क्या नीति को यह हद निर्धारित करनी चाहिए कि पाठ्यचर्या कहाँ तक वैश्विक बनाम स्थानीय हो या विभिन्न प्रदाताओं को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे 'वैश्विक' और 'स्थानीय' के बारे में अपनी धारणा और अपने उद्देश्यों के हिसाब से सुझाव दें तथा माता-पिता या विद्यार्थियों पर यह बात छोड़ दें कि वे किस तरह की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। यह समझना भी जरूरी है कि तनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परस्पर सम्बद्ध हैं और किसी एक के बारे में लिया गया निर्णय अन्य तनावों से निपटने को प्रभावित कर सकता है।

एन.सी.एफ. ने डेलर्स की रिपोर्ट में प्रस्तावित चार स्तम्भों का उल्लेख किया है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रिपोर्ट में 'एक साथ रहना सीखने' को सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ माना गया, जिसका निर्माण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से इक्कीसवीं सदी की वैश्विक चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। बाकी के तीन स्तम्भ जानने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना और अस्तित्व के लिए  सीखना 'एक साथ रहना सीखने' के आधार हैं। अधिगम की समग्र समझ वाली यह बात हमारी शिक्षा प्रणाली में शायद ही आ पाई है। यहाँ तक कि ज्ञान पर जो ध्यान दिया गया है वह भी विद्यार्थियों द्वारा अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने तक सीमित है बजाय इसके कि जानना 'सीखा' जाए और यह सीखा जाए कि कैसे सीखा जाता है। कौशल सीखने और अपनी क्षमताओं को साकार करने से सम्बन्धित स्तम्भ काफी हद तक उपेक्षित रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ, जो एकता के निर्माण और साथ रहना सीखने पर केन्द्रित है, हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा के बाहर लगता है, शायद इसका कारण अन्य तीन स्तम्भों की तुलना में इसका महत्वपूर्ण राजनीतिक स्वरूप है। यहाँ पर यह प्रश्न उठाना उचित होगा कि अधिगम के बारे में हमारी समझ और शिक्षा के उद्देश्यों को इन चार स्तम्भों से किस तरह का महत्वाकांक्षीय मूल्य प्राप्त होगा।

प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इनपुट पर मानव संसाधन मंत्रालय की टिप्पणी में दिए गए कुछ नीतिगत प्रस्ताव भी डेलर्स रिपोर्ट की सिफारिशों को दोहराते हैं। टिप्पणी के विजन में स्थानीय समृद्ध विरासत और प्राचीन ज्ञान की रक्षा करते हुए वैश्विक माँगों को पूरा करने की अत्यावश्यकता की बात कही गई है। इसका उद्देश्य तेजी से बदलते वैश्विक, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के अनुसार कार्य करना है और ऐसा करने में साम्यता और समावेशन के लक्ष्यों को भी ध्यान में रखना है। वैसे तो नीति की टिप्पणी ज्ञान और कौशल के विकास को तनाव के रूप में नहीं देखती लेकिन उन्हें बढ़ाने की बात कहती है। आजीवन अधिगम के लक्ष्य को नीति की टिप्पणी में अनुमोदित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि समाज के सभी खण्डों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

डेलर्स की रिपोर्ट की प्रासंगिकता और अन्तर्दृष्टि के इस चिन्तन का सारांश देते समय यह याद रखना उपयोगी होगा कि हाल में शिक्षा प्रणाली में धीमी गति से ही सही किन्तु निश्चित तौर पर बदलाव आया है। हालाँकि दूसरे देश जिन चुनौतियों और मुद्दों के साथ जूझ रहे हैं, उन्हीं का सामना हमारी शिक्षा प्रणाली भी कर रही है, लेकिन इस रिपोर्ट के योगदान को ध्यान में रखना उपयोगी होगा। अब समय आ गया है कि इसमें की गई बयानबाजी के आधार पर इसे खारिज करने की बजाय हमारा शिक्षा समुदाय इन प्रश्नों पर चर्चा करे और यह देखे कि इन विचारों से हमारी शिक्षा प्रणाली को आकार देने में कैसे मदद मिल सकती है और इस बात की जाँच करें कि हमें वास्तव में क्या सीखना चाहिए।

**अर्चना मेहेंदले** टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुम्बई के सेंटर फॉर एजुकेशन इनोवेशन एण्ड एक्शन रिसर्च में प्रोफेसर हैं। उनसे archana.mehendale@tiss.edu पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद :** नलिनी रावल